जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 35 संख्याः 127 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'ना जात पर, ना पात पर, मोहर लगी हाथ पर'

राहुल गांधी द्वारा ओबीसी तथा ईबीसी को पार्टी की राजनीति का आधार बनाने को पार्टी द्वारा लगातार चुनाव हारने का कारण मानता है, कांग्रेस का बड़ा धड़ा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर। राहुल गांधी की जातिवादी बयानबाजी जिस दिशा में जा रही है और इसकी वजह से जिस तरह से ऊंची जातियां पार्टी से विमुख हो रही है उसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिंतित है।

चिंताजनक बात यह है कि कांग्रेस कभी भी ऐसी पार्टी नहीं रही है, जो किसी विशेष जाति या जातियों से जुड़ी रही हो। ये नेता कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है, लेकिन उसने इसे कभी भी इसे सार्वजनिक रूप से नहीं जताया।

कांग्रेस का स्थायी नारा रहा है, "ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे," जिसका मतलब है कि कांग्रेस हमेशा हर व्यक्ति या महिला के लिए खड़ी रही है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पंथ का हो।

- इस धड़े का मानना है, कांग्रेस सदा सोशल जस्टिस की वकालत तो करती थी अपने कामकाज में, पर, कभी भी सार्वजनिक मंच पर इसका उद्घोष नहीं करती थी।
- इस धड़े का यह भी मानना है कि राहुल गांधी और उनकी टीम, जिसमें एनजीओ, पूर्व आईएएस, कॉर्पोरेट जगत के कुछ भारी भरकम लोग हैं, अव्यवहारिक व "थ्यौरैटिकल पॉलिटिक्स" को ही जानते हैं। पर, अब ये लोग पार्टी को संचालित कर रहे हैं, जिसका उदाहरण है बिहार के प्रभारी अलुवीरा, जो अभी भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि कांग्रेस बिहार में चुनाव बुरी तरह हारी है।
- इस धड़े का कहना है कि पार्टी का नारा हमेशा रहा है, "कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ।" पर, कुछ जातों पर ही फोकस रहने से बाकी जातें, विशेषकर "डोमिनैंट जातें" पार्टी से कट गईं।

राजनीतिक करियर में कई उतार-चढ़ाव देख चुके नेताओं के इस समूह का कहना है कि पार्टी लगातार पराजयों का सामना कर रही है। और ये नेता राहुल गांधी की जातिवादी राजनीति खासकर ओबीसी व दलित की राजनीति को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि ऊँची जातियां ही संसाधनों, ताकत और दबदबे वाली जाति मानी जाती हैं।

यह माना जा रहा है कि बिहार में ब्राह्मणों और अन्य ऊँची जातियों का बहिष्कार कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के ओबीसी और ईबीसी पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया।

कांग्रेस के एक वर्ग का मानना है कि अब समय आ गया है कि पार्टी के पुराने और परखे हुए नारे "कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ" को फिर से अपनाया जाए।

यह नारा समावेशी है, जो जाति या धर्म पर ध्यान नहीं देता बल्कि गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करता है, जो हमेशा से कांग्रेस की रीढ़ रहे हैं।

राज्य दर राज्य यह देखा गया है कि न तो ओबीसी ने और न ही दलितों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन या वोट किया है।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सामाजिक न्याय और सामाजिक इंजीनियरिंग में विश्वास करती रही है, उसने उम्मीदवारों को टिकट देने में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, मतगणना शुक्रवार को

जयपुर, 11 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव गुरुवार को संपन्न हुए। सुबह 8 बजे से शाम पांच बजे तक हुए मतदान में कुल 4745 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतों की गणना शुक्रवार को सुबह 11 बजे से की जाएगी। द बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव भी शुक्रवार को आयोजित किए जाएंगे।

चुनाव अधिकारी दिनेश पाठक ने बताया कि चुनाव में कुल 5538 पात्र मतदाता थे। इनमें से 4745 मतदाताओं ने वोट डाले। हाईकोर्ट परिसर में मिल रही बम विस्फोट की धमकी को देखते हुए मतदान से पहले जांच एजेंसियों ने कोर्ट परिसर की गहनता से जांच की। हर मतदाता को मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद ही प्रवेश दिया गया।

- दी बार एसोसिएशन जयपुर के वार्षिक चुनाव सेशन कोर्ट परिसर में शुक्रवार को होंगे।

चुनाव में अध्यक्ष पद पर छह प्रत्याशी, राजीव कुमार सोगरवाल, महेन्द्र शांडिल्य, अंशुमान सक्सेना, संगीता शर्मा, इन्द्रेश शर्मा व डॉ. रामरूप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मैक्सिको ने भी भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया

भारत से निर्यात किया जा रहा ऑटोमोबाइल, टैक्सटाइल, प्लास्टिक, स्टील व इलैक्ट्रॉनिक साज-सामान, जिसकी गिनती लगभग 400 है, को इस टैरिफ से काफी धक्का लगेगा

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 दिसंबर। मैक्सिको ने जहाँ 400 भारतीय सामानों के आयात पर 50 प्रतिशत सीमा शुल्क (टैरिफ) लगाया है, वहीं अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं तेज़ी से आगे बढ़ी हैं, खासकर अमेरिका के उप-व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विटजर के नेतृत्व में एक टीम के नई दिल्ली पहुंचने के बाद अमेरिकी टीम भारतीय प्रतिनिधियों के साथ व्यापार वार्ताओं को फिर से शुरू करेगी, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी शामिल होंगे।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार समझौते की उम्मीद जताई है। मैक्सिको ने चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया के खिलाफ भी आयात शुल्क की घोषणा की है, लेकिन भारतीय निर्यातकों को, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, वस्त्र, कपड़े, प्लास्टिक, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक

- जानकारी सूत्रों का कहना है, यह टैरिफ मैक्सिको ने अमेरिका के दबाव में लगाया है।
- अमेरिका काफी समय से यह दबाव बना रहा था कि मैक्सिको को यह टैरिफ लगाना चाहिए। क्योंकि काफी समय से भारत, चीन व कुछ अन्य एशियाई देश, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको का रास्ता अपनाते हैं, अपना माल अमेरिका में बेचने के लिए।
- मैक्सिको सितंबर से ही यह टैरिफ लगाने वाला था, इन देशों पर। चीन के भारी विरोध के कारण कुछ समय के लिए यह कोशिश रूक गई थी, पर, अब यह टैरिफ इन एशियाई देशों पर एक जनवरी से लागू हो जाएगा।

उपकरणों जैसे क्षेत्रों में भारी नुकसान हो सकता है।

मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम ने कहा कि यह शुल्क पैकेज घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए है, विशेष रूप से चीन के साथ। मैक्सिको के विधि निर्माताओं ने कहा कि यह कदम स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और सस्ते आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस टैरिफ से लगभग 3.76 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त आय अर्जित होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि मैक्सिको अपने वित्तीय घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है।

विश्लेषकों का कहना है कि यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगर एसआईआर में नाम कटे तो रसोई के औज़ार लेकर मुकाबला करना'

प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर कवायद पर महिलाओं को उकसाते हुए तीखी टिप्पणी की

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 दिसंबर। चुनावाधीन पश्चिम बंगाल में स्पेशल इन्टैन्सिव रिवीजन को लेकर तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अत्यंत तीखी टिप्पणी की और पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में गुरुवार को राज्य की महिलाओं से कहा कि अगर उनके नाम मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान हटाये जाएं तो वे रसोई के उपकरणों के साथ तैयार रहें।

बंगाल के कृष्ण नगर की एक जनसभा में बनर्जी ने कहा, "क्या आप एसआईआर के नाम पर माताओ और बहनो के अधिकार छीनेंगे? वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस लाएंगे और माताओ और बहनो को डराएंगे। माताओ और बहनो, अगर आपके नाम काटे जायें, तो आपके पास रसोई के उपकरण हैं ना। वे उपकरण, जिनका इस्तेमाल आप खाना पकाने में करती हैं। आपके पास ताकत है, ना? अगर आपके नाम काटे जाते हैं तो आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी, है ना? महिलाएं आगे लड़ेंगी, और पुरुष उनके पीछे रहेंगे।"

- ममता बनर्जी ने कहा कि आपके पास ताकत है, अगर वे आपका नाम काटें तो बर्दाश्त नहीं करना।
- बनर्जी ने कहा, मैं देखना चाहती हूँ, कौन ज्यादा ताकतवर है, बंगाल की महिलाएं या भाजपा।
- बनर्जी ने कहा, जब भी चुनाव आते हैं, भाजपा दूसरे राज्यों से लोगों को लाती है, पैसा खर्च करती है और लोगों को बांटती है।

उन्होंने यह भी कहा कि वे देखना चाहती हैं कि कौन अधिक शक्तिशाली है: महिलाएं या भाजपा। "मैं साम्प्रदायिकता में विश्वास नहीं करती। मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हूं। जब भी चुनाव आता है, भाजपा पैसा इस्तेमाल करने और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को विभाजित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में अब 13 जिले होंगे

नई दिल्ली, 11 दिसंबर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली में 11 के बजाय 13 जिले होंगे। इन 13 जिलों और इनके तहत आने वाले सब-डिविजन की लिस्ट भी सामने आ गई है। इसके साथ ही राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं अब एक जैसी होंगी।

जानकारी के मुताबिक, इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद है कि जिलों की प्रशासनिक सीमाएं और नगर निगम के जोन की सीमाएं एक-दूसरे से पूरी तरह मिल जाएं।

- दिल्ली की मु.मंत्री रेखा गुप्ता ने जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने का ऐलान किया और कहा इससे शासन व्यवस्था और सुचारु होगी।

इस बदलाव से एसडीएम कार्यालयों की संख्या 33 से बढ़ कर 39 हो जाएगी। हर जिले में मिनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश में एसआईआर समाप्त, 16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

चुनाव आयोग ने 5 राज्यों व एक केन्द्र शासित प्रदेश में एसआईआर की तारीख बढ़ाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर। चुनाव आयोग ने आज बताया कि वोटर सूची की सफाई करने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की अवधि पाँच राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में बढ़ा दी गई है। ये हैं- तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।

गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए गणना (एन्यूमरेशन) की अवधि 11 दिसंबर को समाप्त हो गई और चुनाव आयोग ने इन राज्यों के लिए समय की कोई बढ़ोतरी नहीं की। चुनाव आयोग ने कहा कि इन चार राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियाँ 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएँगी।

बिहार के बाद, अगला बड़ा राजनीतिक टकराव भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी दलों के बीच बंगाल में होगा, जहाँ अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं।

गणना की संशोधित समय सीमा

- राजस्थान के अलावा गोवा, पुडुचेरी लक्षद्वीप और प.बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया 11 दिसंबर को समाप्त हो गई। इन राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी होगी।
- जिन राज्यों में एसआईआर की अवधि बढ़ाई गई है, उनमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार प्रमुख हैं।

इस प्रकार हैं: तमिलनाडु और गुजरात में 14 दिसंबर; मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर; और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर।

ड्राफ्ट मतदाता सूचियों के प्रकाशन की नई तिथियाँ हैं: तमिलनाडु और गुजरात के लिए 19 दिसंबर; मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार के लिए 23 दिसंबर; और उत्तर प्रदेश के लिए 31 दिसंबर।

इस अवधि -बढ़ोतरी से पहले, चुनाव आयोग ने केरल का कार्यक्रम भी बदला था, जहाँ गणना 18 दिसंबर को समाप्त होगी और ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

यह बढ़ोतरी विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना के बीच आई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने अव्यावहारिक समयसीमा लागू की है, जिससे बूथ लैवल ऑफिसर (बीएलओ) पर भारी बोझ पड़ रहा है और मतदाताओं को भी परेशानी हो रही है।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई (एम) और समाजवादी पार्टी ने एक सर्वदलीय बैठक में कहा कि चुनाव आयोग ने ज़मीनी हकीकतों को नज़रअंदाज़ किया और जल्दबाज़ी में संशोधन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया।

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आयोग से 2003 के पुनरीक्षण में इस्तेमाल किए गए अधिक व्यापक कार्यक्रम को अपनाने की मांग की और चेतावनी दी कि संसद में एसआईआर पर चर्चा न करना यह दिखाता है कि सरकार संसद को चलने देने की इच्छुक नहीं है।

इस सप्ताह की शुरुआत तक, चुनाव आयोग के आँकड़ों के अनुसार, 50.8 करोड़ गणना फ़ॉर्म डिजिटाइज़ किए जा चुके थे। करीब 23.22 लाख फ़ॉर्म अभी भी लंबित हैं। एसआईआर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिगो ने यात्रियों के लिए मुआवज़े की घोषणा की

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर। निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने 03, 04 और 05 दिसंबर को लंबे समय तक हवाई अड्डों पर फंसे रहे यात्रियों के लिए मुआवजा और ट्रैवल वाउचर की घोषणा की है।

एयरलाइंस ने गुरुवार को जारी बयान में इस घटना पर खेद व्यक्त किया है। उसने कहा है कि सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इन यात्रियों को पांच हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक मुआवजा दिया जायेगा। मुआवजे की

- इंडिगो ने 3, 4 और 5 दिसम्बर को हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों के लिए 5 से 10 हजार का मुआवज़ा व दस-दस हजार रु. का ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार के लिए सुखद समाचार, रूस व अमेरिका में यूक्रेन पर समझौता हुआ

मोदी सरकार का तनावपूर्ण दूविधा का समय खत्म, जब सरकार के लिए दोनों ताकतों के बीच संतुलन बैठाना काफी कष्टपूर्ण हो गया था

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर। मोदी सरकार के लिए मास्को और वॉशिंगटन से अच्छी खबर आई है क्योंकि रूस ने आज कहा कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका के साथ उसके मतभेद सुलझा लिए गए हैं, जबकि एक अमेरिकी समाचार रिपोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप की योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत रूस के ऊर्जा प्रवाह को फिर से शुरू किया जाएगा और रुस में प्रमुख अमेरिकी निवेश को चैनलाइज किया जाएगा।

अमेरिका और रूस के बीच मतभेदों का समाधान होने और दोनों देशों के बीच संबंधों का सामान्य होने से, भारत इस दुविधा से मुक्त हो जाएगा कि उसे वॉशिंगटन या मास्को में से किसे आकर्षित करना चाहिए, साथ ही बीजिंग के साथ भारत को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को लेकर पर्याप्त जगह मिलेगी। भारत स्वतंत्र रूप से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगा या रूस से तेल आयात कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका आने वाले दिनों में प्रतिबंधों को हटा सकता है।

रूस पर अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद भारतीय विदेश नीति को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि भारतीय कंपनियों द्वारा रूस से तेल आयात करना वॉशिंगटन के लिए एक बहाना बन गया जिसके आधार पर अमेरिकी सरकार ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ़ के बीच बैठक के बाद सभी "गलतफहमियां" सुलझा ली गई हैं।

- उदाहरण के लिए, जैसा कि विदित ही है, अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, क्योंकि भारत, रूस से तेल खरीद रहा था।
- अमेरिका व रूस के इस समझौते को 1945 की याल्टा कांग्रेस से तुलना की जा रही है, जब सोवियत यूनियन, अमेरिका व ब्रिटेन ने यूरोप में प्रभाव क्षेत्रों को बांटा था।
- अब इस समझौते के बाद, रूस यूरोप को एनर्जी (ऊर्जा गैस व पैट्रोल के रूप में) भेजने के लिए राजी हो गया है तथा यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी तथा रूस व अमेरिका संयुक्त रूप से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी लेंगे।

लावरोव ने कहा कि वार्ताओं ने "आपसी समझ" की पुष्टि की, जो अगस्त में अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान बनी थी।

लावरोव ने कहा, मैं व्यक्तिगत रुप से मानता हूँ कि "अब, अमेरिका के साथ यूक्रेन मुद्दे पर हमारी बातचीत में, गलतफहमियों और संवाद की कमी का समाधान हो गया है।"

रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन में दीर्घकालिक और सतत शांति समझौते को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों के पैकेज की मांग करता है, जिसमें सभी पक्षों के लिए सुरक्षा गारंटी हो।

उन्होंने कहा, "हमने अपने अमेरिकी सहयोगियों को सामूहिक सुरक्षा गारंटी के बारे में अतिरिक्त प्रस्ताव सौंपे हैं, हम समझते हैं कि जब हम सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करते हैं, तो हमें केवल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन को नाटो सदस्यता दिया जाना रुस स्वीकार नहीं करेगा और मास्को यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वालों की सुरक्षा चाहता है।

लावरोव ने कहा कि विटकॉफ़ की यात्रा ने मास्को और वॉशिंगटन के बीच गलतफहमियों को दूर करने में मदद की, हालांकि क्रेमलिन ने उस समय कहा था कि रूस और अमेरिका यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर समझौता नहीं कर पाए थे, जब पुतिन, विटकॉफ़ और जैरेड कुशनर के बीच क्रेमलिन में पांच घंटे की बैठक हुई थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फरार लूथरा बंधु थाइलैंड में गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर। गोवा नाइट क्लब आग हादसे के कुछ ही घंटों बाद भारत से फरार हुए नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें जल्दी ही भारत वापस लाया जाएगा।

विदेश मंत्रालय द्वारा उनके पासपोर्ट सस्पेंड किए जाने के 24 घंटे से भी कम समय बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है । पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक लग

- गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के तुरंत बाद ये दोनों भाई, गौरव व सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। ये दोनों भाई इस नाइट क्लब के मालिक हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)